

धार्मिक तनाव फैलाने वाले नितेश राणे को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए: सांसद वर्षा गायकवाड

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई
भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार में मंत्री पद पर बैठे नितेश राणे लगातार धार्मिक तनाव भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान देना किसी मंत्री को शोभा नहीं देता और यह संविधान व लोकतंत्र का अपमान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और नितेश राणे को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए - मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड ने शनिवार को यह मांग की।



राजीव गांधी भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम तनाव फैलाना ही मानो नितेश राणे का एकमात्र काम बन गया है। आज भी उन्होंने एक समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह बयान दिया कि मद्रसे आतंकवादी तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें बंद कर देना चाहिए। यह बयान बेहद गैरजिम्मेदाराना और भड़काऊ है। गायकवाड ने आगे कहा, नितेश

राणे की जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे लगातार एक धर्म के खिलाफ ज़हर उगलते रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो यह माना जाएगा कि वे राणे के बयानों का समर्थन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नितेश राणे को यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मंत्री पद संभाला है और उन्हें समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, न कि विभाजनकारी राजनीति करनी चाहिए।

भाषा विवाद पर भी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद वर्षा गायकवाड ने कहा कि मराठी और हिंदी भाषा के मुद्दे पर कुछ लोग केवल अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस को किसी भी भाषा से विरोध नहीं है। हमें मराठी भाषा पर गर्व है और कांग्रेस की स्पष्ट भूमिका है कि शालेय शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि सरकार ने इस संबंध में दो जीआर (शासन निर्णय) निकाले थे, लेकिन जनता के विरोध को देखते हुए उन्हें रद्द करना पड़ा। अब उन पुराने निर्णयों को लेकर फिर से विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाषा को लेकर मारपीट करना भी गलत है।

संभाजी भिडे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोलते हैं। भारत का संविधान और तिरंगा झंडा आरएसएस ने कभी स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता के ५० सालों तक आरएसएस के दफ्तरों पर तिरंगा नहीं फहराया गया। आज भी वे संविधान को नहीं मानते। वे मनुवादी विचारधारा के समर्थक हैं।

अंत में गायकवाड ने कहा कि जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर ऐसे विवादित मुद्दे उछाले जा रहे हैं।

घरकुल के लिए पात्र लाभार्थी स्वयं करें सर्वेक्षण-विधायक संदीप क्षीरसागर

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घरकुल (प्रधानमंत्री आवास योजना) के सेल्फ सर्वे की अंतिम तिथि ३१ जुलाई तक बढ़ी

बीड, १९ जुलाई (प्रतिनिधि): प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को नए घरकुल (पक्के मकान) मिलने वाले हैं। इसके लिए ऑनलाइन सेल्फ सर्वे करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब ३१ जुलाई कर दी गई है। नागरिक ३१ जुलाई तक मोबाइल ऐप के माध्यम से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं।

इसलिए बीड विधानसभा क्षेत्र के बीड और शिरूर कासार तालुकों के जिन पात्र नागरिकों ने अब तक सर्वे नहीं कराया है, वे अपने मोबाइल से या ग्रामसेवक की मदद से ३१ जुलाई से पहले सेल्फ सर्वेक्षण अवश्य कर लें - ऐसा आह्वान विधायक संदीप क्षीरसागर ने किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने के लिए फिलहाल सेल्फ सर्वेक्षण की प्रक्रिया जारी है। इसके अंतर्गत आप ग्रामसेवक या पंचायत अधिकारी की मदद से, या स्वयं अपने मोबाइल से सर्वेक्षण करके पंजीकरण कर सकते हैं।

जिन लोगों के पास कच्चा मकान है और जो पात्र हैं, वे इस योजना के लिए सेल्फ सर्वे अवश्य करें। इसके



लिए सरकार ने अंतिम तिथि ३१ जुलाई २०२५ निर्धारित की है। इसके पहले बीड विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपना सर्वेक्षण पूरा करें।

सेल्फ सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया:
१. सबसे पहले -waas Plus-२०२४ नामक सरकारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें।
२. इसके बाद -रवहरी Face RD ऐप भी इंस्टॉल करें।
३. फिर ऐप पर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और पृष्ठों पर सारी जानकारी भरें।
४. अंत में अपने कच्चे मकान की फोटो और नया घर बनाने की जगह की फोटो अपलोड करें।

५. आधार और जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन करवाकर सर्वे को अपलोड करें।

अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या तकनीकी प्रक्रिया करने में कठिनाई हो रही है, तो अपने गांव के ग्रामसेवक की मदद से भी यह सर्वे करवा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।

अंधेरी के मैन्ग्रोव कटाई पर तत्काल संज्ञान; सत्र समाप्त होते ही पंकजा मुंडे ने की स्थल पर जाकर जांच

अवैध भराव करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के पर्यावरण मंत्री के आदेश

मुंबई, १९ जुलाई: जमीर काज़ी
अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला बैंक रोड क्षेत्र में मैन्ग्रोव (कांदळवन) की हो रही अवैध कटाई के मामले में महाराष्ट्र की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने तुरंत घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की गंभीरता का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अवैध रूप से भराव करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और वहां से भराव हटाकर मूल मैन्ग्रोव वनस्पति की पुनः स्थापना करने के आदेश दिए।

यह निरीक्षण विधानभवन में विधायक अनिल परब द्वारा दिए गए लक्ष्यवेधी सूचना पर दिए गए आश्वासन की पूर्ति के रूप में किया गया। विधानमंडल सत्र के समाप्त होने के दूसरे ही दिन पंकजा मुंडे खुद घटनास्थल पर पहुंचीं।



सी.टी.एस. नंबर १६९, पहाड़ी गोरेगांव क्षेत्र में किए गए इस निरीक्षण में विधायक अनिल परब, पर्यावरण विभाग की सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (चज़उड) के सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि बफर जोन में बिना किसी अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध

भराव किया गया है। पर नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से देखा गया। मंत्री पंकजा मुंडे ने यह भी सवाल उठाया कि कुछ वर्ष पहले यह जमीन नॉन-डेवलपमेंट जोन में थी, तो अब यह डेवलपमेंट जोन कैसे घोषित हो गई? उन्होंने इस पर विभाग को निर्देश दिया कि जमीन की पूर्व स्थिति और बदलाव के कारणों की तहकीकात कर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।

इसके साथ ही, जो ठेकेदार इस अवैध भराव के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर तुरंत आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, अवैध रूप से डाले गए भराव को हटाकर वहां मूल मैन्ग्रोव वन को बहाल करने के आदेश भी उन्होंने दिए।

मैन्ग्रोव वनस्पति की अवैध कटाई और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, पंकजा मुंडे ने सभी ऐसे मामलों को संकलित कर तुरंत कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा,

इस तरह की घटनाएं अब रुकनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रशासन को तेजी से और प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।

गुजरात के सांसदों ने २५४ करोड़ में से सिर्फ ३.५ करोड़ रुपये खर्च किए

९६.८% फंड अभी भी नहीं हुआ इस्तेमाल: खोखले विकास का दावा

अहमदाबाद से शेख हबीब की रिपोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खुद गुजरात से लोकसभा और राज्यसभा में चुने गए उनके सांसदों ने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए मिले करोड़ों रुपये का अभी तक उपयोग नहीं किया है।

गुजरात के कुल २६ सांसदों को केंद्र सरकार द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए २५४.८ करोड़ रुपये

आवंटित किए गए थे। इन सांसदों की सिफारिश पर यह फंड उपयोग में लाया जाता है, लेकिन आरटीआई के जरिए सामने आई जानकारी के मुताबिक ५ जुलाई २०२५ तक केवल १०.७२ करोड़ रुपये के ही प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, यानी कि २४४.०८ करोड़ रुपये अब भी खर्च नहीं किए गए हैं।

बीजेपी के २५ और कांग्रेस के १ सांसद गुजरात से हैं, लेकिन लाखों-करोड़ों रुपये की इस रकम को विकास कार्यों में

खर्च नहीं किया गया है।

सबसे चौंकाने वाला मामला नवसारी से सांसद और केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल का है, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में २९७ विकास कार्यों की सिफारिश की गई थी, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ।

महसाणा के सांसद हरीभाई पटेल ने २७१ प्रोजेक्ट्स और खेड़ा के सांसद देवसिंह ने २६५ विकास कार्यों की सिफारिश की, लेकिन अब तक कोई

ठोस काम ज़मीन पर नहीं दिखाई देता, जबकि फंड उपलब्ध है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यही है उनका तथाकथित गुजरात विकास मॉडल - सिर्फ बातें करना, बड़े-बड़े दावे करना और जनता को गुमराह करके वोट बटोरना।

एक साल में गुजरात के सांसदों ने कुल ३८२३ विकास कार्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सिर्फ ९३ पर ही अमल हुआ।

बारडोली क्षेत्र में सबसे ज्यादा २९ काम पूरे किए गए, जबकि अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट के लिए १४८ प्रोजेक्ट्स की सिफारिश की गई थी - लेकिन एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ।

जनता के कामों में लापरवाही का आलम यह है कि सांसद सिर्फ लिखकर और घोषणा करके चुप हो जाते हैं। वे यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने तो लिखा है, सरकार से मंजूरी नहीं मिली तो हम क्या करें? लेकिन वे यह भूल

जाते हैं कि केंद्र में भी उनकी ही सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं, फिर भी विकास कार्य ठप हैं।

अगर खुद प्रधानमंत्री के राज्य गुजरात की यह हालत है, तो अन्य राज्यों के सांसदों का क्या हाल होगा?

भले ही मोदी सरकार और भाजपा पूरे देश में गुजरात को एक आदर्श राज्य (मॉडल स्टेट) के रूप में प्रचारित करते हों, लेकिन हकीकत यही है कि बिना रिश्त दिये जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

‘विधानसभा चुनाव में हमारे बीच का मैं’ आड़े आया-उद्धव ठाकरे

पराजय का ठीकरा महाविकास आघाड़ी पर फोड़ा।



रिपोर्ट: जमीर काजी, मुंबई
लोकसभा चुनाव हम' के भाव से लड़े इसलिए महाविकास आघाड़ी (चत-) को सफलता मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैं' पन आ गया, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा - यह खुला स्वीकारोक्ति पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दी है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसी गलतियां दोबारा होती हैं, तो साथ आने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
सांसद संजय राऊत द्वारा उद्धव ठाकरे का लिया गया विस्तृत इंटरव्यू का पहला भाग शनिवार को सामना' में प्रकाशित

हुआ। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, 'ठाकरे ब्रैंड', राज ठाकरे के साथ गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की आंतरिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा की।
जब उनसे लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद विधानसभा चुनाव में करारी हार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा:
ईवीएम घोटाले की चर्चा चल रही है, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और फर्जी वोटरों की बात भी सामने आई है।
उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे विधानसभा क्षेत्र छोटे होते हैं, प्रतियोगिता बढ़ती है और गठबंधन में शामिल दो-तीन दलों के बीच खींचतान शुरू हो जाती है।
हमने लोकसभा चुनाव चत- के रूप में लड़ा। उस समय शिवसेना ने भी अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी थीं। लेकिन

विधानसभा में आखिरी वक्त तक खींचतान चलती रही। इसका जनता पर नकारात्मक असर पड़ा। लोगों को लगा कि अभी से आपस में झगड़ा हो रहा है, तो आगे क्या होगा?
उन्होंने यह भी कहा कि: लोकसभा में मेरे पास उम्मीदवार थे, सीटें थीं, लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं था। विधानसभा में चिन्ह था, लेकिन सीटें नहीं थीं। यह तय नहीं था कि जो सीटें मिलेंगी, उनमें टिकट किसे दिया जाएगा। यही 'तू-तू, मैं-मैं' हुई जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर यही गलती फिर दोहरानी है, तो साथ आने का कोई औचित्य नहीं है।
लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक हम सबको मिलकर जीतना है' का भाव था, जबकि विधानसभा में मुझे जीतना है' की

मानसिकता आ गई - और यही मैं' पन हार का कारण बना, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुछ तकनीकी कारण भी हार के लिए जिम्मेदार थे।
सरकार पर हमला करते हुए ठाकरे ने कहा:
हाल के दिनों में सत्ता का घमंड साफ नजर आ रहा है। हमने विधायक की बाक्सिंग देखी, विधानभवन परिसर में मारपीट हुई - ये घटनाएं महाराष्ट्र को शर्मिंदा करने वाली हैं। अगर विधानसभा परिसर में गुंडागर्दी होगी तो यह स्थिति राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसी गंभीर मानी जानी चाहिए।
गुंडों को पद से हटाने की अपील उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी दलों को मिलकर पार्टी में मौजूद गुंडों को पद से हटाना चाहिए। अगर विधानभवन

परिसर में ही राडा मचाया जाएगा तो देश में महाराष्ट्र की छवि क्या बनेगी?
पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर लोकतंत्र का खून करने वाले लोग विधानसभा में घूमने लगेंगे, तो जनता क्या करे? - ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया। मनसे के साथ गठबंधन पर बोले:
बीस सालों बाद हम पहली बार एक मंच पर आए हैं। और वह भी मराठी भाषा के मुद्दे पर। मैंने तब भी कहा था कि हम एक साथ आए हैं - तो साथ रहेंगे। हम मराठी के मुद्दे पर एकजुट रहेंगे। राजनीतिक गठबंधन की बात आगे की है - अभी कोई चुनाव घोषित नहीं हुआ है। जब चुनाव घोषित होंगे, तब हम उस पर चर्चा करेंगे।
ठाकरे ने स्पष्ट किया कि हम किसी भाषा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम किसी भी भाषा को जबरदस्ती थोपने की इजाजत नहीं देंगे।

समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध-राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक



बीड, १९ जुलाई (जिमाका): राज्य में हर समाज के समग्र विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बंजारा समाज के भी अनेक प्रश्न हैं और उन्हें हल करने के लिए सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है - यह प्रतिपादन उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक ने किया।
वे गेवराई स्थित भाग्यलक्ष्मी मंगल कार्यालय में आयोजित गोर बंजारा समाज के एकता मेळावा को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की जयंती के अवसर पर किया गया था।
इस मौके पर विधायक विजयसिंह पंडित, मुख्यमंत्री सहायता निधि प्रमुख रामेश्वर नाईक, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडल के सहआयुक्त विजय राठौड, साहेबराव शास्त्री महाराज, सचिन महाराज, चैतन्य महाराज, अमरसिंह पंडित, नाईक फाउंडेशन की मोहिनीताई इंद्रनील नाईक, उत्तम चव्हाण, प्रो. पी.टी. चव्हाण, बाबूराव जाधव, अण्णासाहेब राठौड, राजेश पवार, सतीश पवार, अनिल राठौड आदि उपस्थित थे।
कार्यक्रम में राज्य स्तरीय बंजारा भूषण

पुरस्कार गोर समाज की ओर से राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक को प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य लोकसेवा आयोग, दसवीं, बारहवीं, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को भी राज्यमंत्री नाईक के हाथों सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर अमरसिंह पंडित, उत्तम चव्हाण, पी.टी. चव्हाण, रामेश्वर नाईक, साहेबराव शास्त्री, और मोहिनी नाईक ने अपने विचार व्यक्त किए।
कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। प्रस्तावना उत्तम चव्हाण ने प्रस्तुत की और सूत्र संचालन राहुल गिरी ने किया। गेवराई एमआयडीसी पर बैठक जल्द आयोजित होगी
इस अवसर पर उद्योग राज्यमंत्री नाईक ने आश्वासन दिया कि गेवराई एमआयडीसी से संबंधित बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गांव-तांडा तक सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए शासन निरंतर प्रयासरत है।

सांसद सोनवणे के प्रयासों से दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा कृत्रिम उपकरण

मुफ्त उपकरणों के लिए दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित रहें: खुर्शीद आलम

बीड (प्रतिनिधि): जब से बजरंग बप्पा सोनवणे बीड से सांसद बने हैं, तब से बीड जिले में आम नागरिकों के हित में अनेक कार्य दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग और एलिम्फो मुंबई के संयुक्त उपक्रम द्वारा बीड तालुका के दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कृत्रिम उपकरण वितरण के उद्देश्य से दिनांक २१ जुलाई को सुबह १० बजे से शाम ५ बजे तक पंचायत समिति बीड कार्यालय में पूर्व जांच शिविर का आयोजन किया गया है।
इस शिविर का उद्घाटन सांसद बजरंग बप्पा सोनवणे के हाथों किया जाएगा। इस अवसर पर सभापति खुर्शीद आलम ने अपील की है कि सभी दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
शिविर में मिलने वाले उपकरणों में शामिल हैं: दिव्यांगों के लिए: जयपुरी फुट, कृत्रिम हाथ-पैर, व्हीलचेयर, ट्रायसिकल, क्रूचेस, वॉकिंग स्टिक, ब्रेल किट, स्मार्टफोन, श्रवण यंत्र आदि वरिष्ठ नागरिकों के लिए: बेल्ड, वॉकर, छड़ी, चश्मे, कृत्रिम दांत, सहारा देने वाली खुबड, कृत्रिम अंग, कान की मशीन, व्हीलचेयर कमोड, सिलिकॉन तकिया, नी सपोर्ट, स्प्राइनल सपोर्ट, सर्वाइकल कॉलर आदि शिविर में लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज: दिव्यांग नागरिकों के लिए: यू.आई.डी. कार्ड (आधार कार्ड) सालाना आय प्रमाण पत्र / राशन कार्ड आय सीमा: मासिक २२,५०० या सालाना २,७०,००० के भीतर वरिष्ठ नागरिकों के लिए: आधार आय प्रमाण पत्र / राशन कार्ड आय सीमा: मासिक १५,००० या सालाना १,८०,००० के भीतर इन सभी दस्तावेजों को साथ लेकर शिविर में उपस्थित रहने की अपील राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के शहराध्यक्ष एवं मा. सभापति खुर्शीद आलम ने की है।

डांस कीन स्वाति देव और चॉकलेट हीरो सुरेश सालुंके की अदाओं पर झूम उठा वरिष्ठ नागरिकों का नृत्य मंच



जब वरिष्ठ नागरिक कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे, तब डॉ. दीपा क्षीरसागर कार्यक्रम का आनंद लेते हुए अपने मोबाइल से फोटो भी ले रही थीं। उनकी इस रसिकता को देखकर कलाकार बेहद प्रसन्न हो उठे।

बीड: संवादाता अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद शाखा बीड और सी. के.एस.के. महाविद्यालय के नाट्यशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संध्याकाल में आओ यूँ ही, मदहोश सी दिशाएँ... इस शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में १९७५ से १९८० के दशक के मेलों में डांस कीन और चॉकलेट हीरो के रूप में प्रसिद्ध रही स्वाति देव और सूत्रधार सुरेश सालुंके ने १९५७ की दिलीप कुमार और वैजयंती माला अभिनीत फिल्म नया दौर के अमर गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी पर बेहद रोमांटिक

अंदाज़ में डांस प्रस्तुत कर माहौल को रंगीन बना दिया। इस सदाबहार रोमांटिक डांस की कोरियोग्राफी खुद चॉकलेट हीरो सुरेश सालुंके ने की। गीत में मौजूद बारीक-बारीक रोमांटिक और शरारती हिस्सों को सुरेश सालुंके ने भावों के साथ पेश किया, तो उतनी ही खूबसूरती से डांस कीन स्वाति देव ने उन्हें अपने भावपूर्ण नृत्य से जीवंत कर दिया। गीत के हर शब्द के साथ बदलते उनके रोमांटिक, मस्तमौला और चुलबुले हाव-भाव ने इस प्रस्तुति को ऊँचाई तक पहुँचाया। इसलिए थिएटर में तालियाँ और सीटियों के साथ उत्साही प्रतिसाद मिल रहा था। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पाटोदा, गेवराई, अंबाजोगाई जैसे स्थानों से वरिष्ठ नागरिक कलाकार भी विशेष रूप से उपस्थित थे।
कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. सौ. सारिका क्षीरसागर, प्राचार्य शिवानंद क्षीरसागर तथा उपप्राचार्य डॉ. संजय पाटील की प्रमुख उपस्थिति में डॉ. दीपा क्षीरसागर के शुभहस्तों संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की योजना और सूत्र संचालन नाट्यशास्त्र विभाग के डॉ. दुष्यंत रामटेके और इतिहास विभाग की प्रमुख डॉ. अनीता शिंदे ने किया। उन्हें संगीत विभाग के डॉ. राहुल सोनवणे, प्रा. दीपक जमधाड़े, प्रा. सुरेश थोरात, प्रा. इंद्रजीत भांगे, प्रा. पवन शिंदे और नाट्यशास्त्र विभाग के डॉ. विजय राख का सहकाय मिला।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, रसिकजन और कला प्रेमी उपस्थित थे।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं के योगदान पर राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन (वेबिनार) का आयोजन किया

नई दिल्ली, १९ जुलाई : जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के महिला विभाग ने भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं का योगदान विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन में प्रतिष्ठित सामाजिक विचारकों ने भाग लिया, जिन्होंने भारत के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में उन मुस्लिम महिलाओं के असाधारण योगदान पर चर्चा की गयी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वेबिनार में एकीकृत अनुसंधान, कहानी और आत्मनिरीक्षण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जमाअत की राष्ट्रीय सचिव रहमतुनिसा ए ने की। वह महिला नेतृत्व एवं सुधार की प्रमुख समर्थकों में से हैं।
वेबिनार में मुख्य सम्बोधन दक्षिणी न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय और सेंट लियो विश्वविद्यालय सहित कई अंतरराष्ट्रीय

विश्वविद्यालयों में भारत संकाय पर्यवेक्षक डॉ. संगीता सक्सेना ने किया। उन्होंने बिहार और बंगाल के विशाल ऐतिहासिक अभिलेखों का उपयोग करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक सुधार, साहित्य और व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली मुस्लिम महिलाओं की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की। बेगम हजरत महल से लेकर ज़हारा कलीम तक, उन्होंने उन महिलाओं को रेखांकित किया, जो पाठ्यपुस्तकों से अनुपस्थित होने के बावजूद, हमारे देश के इतिहास में गुमनाम नायिकाएं रहीं। डॉ. तुहिना इस्लाम, सहायक प्रोफेसर, आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता ने अलीगढ़ महिला कॉलेज की अग्रणी वाहिद जहां बेगम के कार्य और जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी शोधपरक प्रस्तुति में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में वाहिद जहां के दूरदर्शी कार्यों और मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक शिक्षण वातावरण प्रदान करने में

उनके त्याग पर प्रकाश डाला गया। उनका योगदान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और सशक्त है।
दोनों वक्ताओं ने मुस्लिम महिलाओं के समक्ष उत्पन्न दोहरे बोझ सार्वजनिक चिंता का अभाव और पितृसत्तात्मक संस्कृति की बाधा को दूर करने में असमर्थता की ओर इशारा किया। उन्होंने विद्वानों और युवा पीढ़ी को घरेलू स्तर पर अपना अध्ययन शुरू करने की चुनौती दी, क्योंकि मौखिक इतिहास और अपने आसपास की महिलाओं के विस्मृत जीवन के माध्यम से वे घर पर ही अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं। श्रीमती रहमतुनिसा ए ने लोगों को विश्व के बदलते स्वरूप की जांच में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। उन्होंने जोर देकर कहा, इतिहास को केवल इतिहास की कहानी न बनने दें। उन्होंने वर्तमान युग में इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से ऐतिहासिक

आख्यानों में हेरफेर करने के लिए बढ़ते संस्थागत प्रयासों के आलोक में।
श्रीमती रहमतुनिसा मुस्लिम महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, महिलाओं का विभिन्न पीढ़ियों में समाज में योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद के काल में, भारत के इतिहास में मुस्लिम महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान, उनकी कहानियों को सामने लाने की आवश्यकता है। उन्होंने हमारे अतीत के असली नायकों को उजागर करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए और अधिक अकादमिक शोध की आवश्यकता पर भी बल दिया।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महिला विभाग की सहायक सचिव सुमैय्या मरियम ने सम्मेलन का समन्वय किया, जिसमें देश भर के विद्वानों,

शिक्षकों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भाग लिया। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महिला विभाग की सहायक सचिव राबिया बसरी ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें भारतीय मुस्लिम महिलाओं की अक्सर अनदेखी की गई उपलब्धियों को पहचानने की आवश्यकता और उनकी आवाज को पुनर्जीवित करने के लिए जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। जमाअत की महिला राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य मीनाज़ भानू ने कार्यक्रम का संचालन किया और भारत के सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया।
ऐसे समय में जब इतिहास को मिटाना एक बढ़ती हुई समस्या है, यह सम्मेलन न केवल अकादमिक दृष्टि से प्रभावशाली था, बल्कि इसमें नैतिक अनिवार्यता, उद्देश्य-संचालित प्रेरणा भी थी। यह सम्मेलन मुस्लिम महिलाओं की विरासत को आवश्यक राष्ट्र-निर्माता के रूप में

मान्यता देने, उसका दस्तावेजीकरण करने और उसका स्मरण करने के लिए है। यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों पर नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है, जिनमें मुगल क्रूरता और मंदिर विध्वंस को उजागर किया गया है तथा एक पक्षपातपूर्ण कथा को बल दिया गया है, जिसमें मुस्लिम शासकों को भारत में बसने और विकास करने वाले शासकों के बजाय विदेशी आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया गया है। इस तरह के पक्षपातपूर्ण आख्यान से सदियों से चले आ रहे जटिल शासन को धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष के कृत्यों में बदलकर भारत के मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक भूमिका के रूप में चित्रित करने का खतरा है।
द्वारा जारी : सलमान अहमद राष्ट्रीय सचिव, मीडिया विभाग, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, मुख्यालय